

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 478 का उत्तर

रेलगाड़ियों का निजीकरण

478. श्री मनोज तिवारी:
श्री उदय प्रताप सिंह:
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री के. सुब्बारायण:
श्री हरीश द्विवेदी:
श्री ए. राजा:
श्री गौरव गोगोई:
श्री एम. सेल्वराज:
श्री बैन्नी बेहनन:
श्री एस. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार अन्य कॉर्पोरेट्स को तेजस एक्सप्रेस की तरह देश के भीतर लक्जरी रेल शुरू करने की अनुमति दे रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने देशभर में निजी ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए और अधिक मार्गों की पहचान करने के लिए सचिवों का शक्ति प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया है और क्या 24 संभावित मार्गों की पहचान की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार इच्छुक और योग्य संस्थाओं से बोली कब तक आमंत्रित करने की योजना बना रही है;
- (च) क्या कुछ राज्यों में इसका विरोध किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार का क्या रुख है; और
- (छ) क्या निजीकरण के परिणामस्वरूप रेल टिकटों का किराया बढ़ता है और यदि हां, तो क्या रेलवे में विभिन्न श्रेणियों से इन मार्गों में यात्रा करने वाले नागरिकों को राजसहायता दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): रेल मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रेल नेटवर्क पर विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के साथ निजी यात्री गाड़ी संचालकों को गाड़ियों के संचालन की अनुमति देने के लिए सचिवों के एक दल (जीओएस) का गठन किया है, जिसके विचारार्थ मुख्य विषय निम्नानुसार हैं:-

- i. बोली दस्तावेजों सहित बोली प्रक्रिया का अनुमोदन करना; और
- ii. बोली प्रक्रिया की निगरानी करना और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सौंपने को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेना।

अब तक, जीओएस की तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और इसलिए, मार्गों, किराया संरचना, सब्सिडी, आदि से संबंधित तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यात्री गाड़ियों के निजीकरण के संबंध में दो मान्यता प्राप्त रेलवे कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलों में उनकी संबद्ध ट्रेड यूनियनों और अन्य ट्रेड यूनियनों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
